भारत सरकार
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2797
जिसका उत्तर 6 अगस्त, 2025 को दिया जाना है।
15 श्रावण, 1947 (शक)

स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य

2797. श्री रमासहायम रघुराम रेड्डीः

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत 2026 तक 250-300 बिलियन डॉलर के स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा और अनुमान वर्षवार क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(ग):** मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत पिछले 11 वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का उल्लेखनीय रूप से विस्तार हुआ है। सरकार आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स पारिस्थितिकी तंत्र को सक्रिय रूप से मज़बूत कर रही है।

हाल के वर्षों में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इकाइयों द्वारा मूल्यवर्धन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसे निम्नलिखित आँकड़ों से देखा जा सकता है:

#	2014-15	2024-25	टिप्पणी
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का उत्पादन (रु.)	1.9 लाख करोड़	11.3 लाख करोड़	6 गुना वृद्धि
इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं का निर्यात	0.38 लाख करोड़	3.3 लाख करोड़	8 गुना वृद्धि
मोबाइल विनिर्माण इकाइयाँ	2 इकाइयाँ	300 इकाइयाँ	150 गुना वृद्धि
मोबाइल फोन का उत्पादन (रु.)	0.18 लाख करोड़	5.5 लाख करोड़	28 गुना वृद्धि
मोबाइल फोन का निर्यात (रु.)	0.01 लाख करोड़	2 लाख करोड़	127 गुना वृद्धि
आयातित मोबाइल फोन (कुल इकाइयों का %)	मांग का 75%	मांग का 0.02%	

सरकार घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उच्च पूंजी, उत्पादन के पैमाने, लंबी अवधि, नवीनतम तकनीकों और कौशल की आवश्यकता के प्रति भी सचेत है। इनसे निपटने के लिए शुरू की गई विभिन्न रणनीतिक पहलें निम्नलिखित हैं।

- बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई)
- आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई)
- इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टर्स के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीईसीएस)
- इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (ईएमसी और ईएमसी 2.0) योजना
- सार्वजनिक खरीद में घरेलू स्तर पर निर्मित उत्पादों को प्राथमिकता देने के लिए सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017
- कराधान में सुधार, जिसमें टैरिफ संरचना का युक्तिकरण, पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क में छूट आदि शामिल हैं।
- लागू कानूनों/विनियमों के अध्यधीन, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में 100% एफडीआई की अनुमति देना।

******